डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 मार्च से 15 मार्च, 2022, डिस्पेच दिनांक 16 मार्च, 2022

| वर्ष 65 | अंक 19 | भोपाल | 1 मार्च, 2022 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

इंदौर मॉडल शहरों को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त करने अन्य शहरों के लिए बनेगा प्रेरणा - प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

मुख्यमंत्री श्री चौहान और उनकी टीम ने कम समय में बड़ा काम कर दिखाया

इंदौर की बहनों का कूड़ा प्रबंधन अनुकरणीय

मैं दिल्ली से इंदौर के सफाई कर्मियों को नमन करता हूँ

स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतरीन मॉडल बन कर उभरा है इंदौर

स्वच्छता अभियान को नई ताकत देगा बायो सीएनजी गोबर-धन प्लांट

6 प्रकार के कचरे को 100% अलग-अलग करने वाला अद्भुत शहर है इंदौर

किसान अब अन्नदाता के साथ बन रहे हैं ऊर्जादाता

प्रधानमंत्री श्री मोदी की सर्कुलर इकोनामी और "वेस्ट टू वेल्थ" परिकल्पना को मध्यप्रदेश ने दिया मूर्त रूप - मुख्यमंत्री

भोपाल : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरों को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त करने का इंदौर मॉडल अन्य शहरों के लिए प्रेरणा बनेगा। इंदौर के देवगुराड़िया क्षेत्र में कभी कूड़े के पहाड़ थे, अब वहाँ 100 एकड़ की डंप साइट ग्रीन जोन में परिवर्तित हो गई है। इंदौर में गोबर-धन बायो सीएनजी प्लांट बनने से वेस्ट-टू-वेल्थ तथा सर्कुलर इकोनामी की परिकल्पना साकार हुई है। इससे भारत के स्वच्छता अभियान भाग-2 को नई ताकत मिलेगी, जिसके अंतर्गत आने वाले 2 वर्षों में देश के सभी शहरों को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त कर ग्रीन जोन बना दिया जाएगा। इंदौर शहर ने वाटर प्लस की भी उपलब्धि हासिल की है, अब यह शहर देश के अन्य शहरों को इस क्षेत्र में भी प्रेरणा देगा। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी टीम ने बड़ा काम कर दिखाया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इंदौर में गोबर-धन बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण कर रहे थे। मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल, केंद्रीय, सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार, आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर, राज्य शासन के मंत्री, सांसद, विधायक सहित जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इंदौर की बहनों ने कूड़ा प्रबंधन का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कूड़े को 6 हिस्सों में अलग-अलग बाँट कर उसका निस्तारण किया है। यह री-साइकिलिंग संस्कार, देश की बड़ी सेवा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इंदौर के सफाईकर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना के मुश्किल समय में उनकी सेवा सराहनीय है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

प्रमुख सचिव सहकारिता बनाए गए केसी गुप्ता

भोपाल। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी श्री के.सी. गुप्ता जी को सहकारिता विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को पदस्थापना आदेश जारी किया और उन्होंने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी अभी तक अपर मुख्य सचिव श्री अजीत केसरी सम्भाल रहे थे। उनके पास अब कृषि विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। कृषि शिवराज सरकार की प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। जैविक कृषि विस्तार के साथ कई नवाचार विभाग द्वारा किये जा रहे है। इसे देखते हुए इन्हें सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी से मुक्त किया है।

अपने आप में सम्पूर्ण और मानवीय भावनाओं से भरपूर हों प्रदेश के शहर : मुख्यमंत्री श्री चौहान

रोजगार युक्त, विकसित और स्वच्छ हों हमारे शहर

50 हजार हितग्राहियों का गृह प्रवेश, 30 हजार नवीन आवासों का भूमि-पूजन और 26 हजार 500 हितग्राहियों के खाते में 250 करोड़ रुपये हुए अंतरित

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारा यह प्रयास है कि प्रदेश के शहर, अपने आप में संपूर्ण और मानवीय भावनाओं से भरपूर हों। इसके लिए आवश्यक है कि शहर स्वच्छ हों, शहर में कोई बच्चा भूखा नहीं रहे, कोई बच्चा अनाथ नहीं घूमे, शहर में हम पेड़ लगाएँ और शहरों का जन्म-दिवस या गौरव दिवस मनाएँ। इन गतिविधियों से हमारे शहर इंसानियत से भरपूर बनेंगे। प्रयास हो कि हमारे शहर केवल सीमेंट-कंक्रीट के नगर न हों, अपितु उनमें स्नेह, प्रेम और आत्मीयता की भावनाएँ निवास करें। इन संकल्पों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने कई कार्य आरंभ किए हैं। इनमें रैन बसेरों का सुदृढ़ीकरण, पेयजल एवं सीवरेज योजनाओं का विस्तार, सड़कों का सुधार शामिल है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में लोगों की जिंदगी बदलने का कार्य जारी है।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

किसानों के हक और हितों के बीच किसी को बाधा नहीं बनने देंगे - राज्य मंत्री श्री कुशवाह

किसानों के सुझावों को बजट में करेंगे शामिल

भोपाल : उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि किसानों की मेहनत का प्रतिफल पिछले वर्षों में मिले कृषि कर्मण अवार्ड हैं। प्रदेश के किसानों के हक और हितों के बीच किसी प्रकार की बाधा को नहीं आने दिया जायेगा। राज्य मंत्री श्री कुशवाह उद्यानिकी विभाग की संभाग-स्तरीय एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। गुलाब उद्यान के सभाकक्ष में हुई कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी श्री जे.एन. कंसोटिया और भोपाल संभाग के सभी जिलों के उद्यानिकी अधिकारी और कृषक मौजूद थे। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि राज्य सरकार किसानों से प्राप्त सुझावों के आधार पर बजट तैयार करेगी। किसानों से उनके सुझाव प्राप्त करने के लिये संभाग-स्तरीय कार्यशालाएँ हो रही हैं। इसमें उद्यानिकी कृषकों के हित और उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिये जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, उन पर गंभीरता से विचार किया जायेगा।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि किसानों के सुझावों को सरकार की नीति में भी शामिल कराने पर पहल की जायेगी। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि किसानों के सुझाव लेने वह खुद किसानों के बीच आये हैं। अपर मुख्य सचिव श्री कंसोटिया ने उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक बेहतर करने के लिये जिलों में कार्य करने वाले अधिकारियों से भी सुझाव देने के लिये कहा।

किसानों ने दिये सुझाव

किसानों ने खेती के व्यवहारिक अनुभव को साझा करते हुए उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और उद्यानिकी कृषकों के हितों के संबंध में सुझाव दिये। उद्यानिकी कृषकों को समय पर उच्च गुणवत्ता के फसलों के बीज उपलब्ध कराने अथवा किसानों को स्वयं मार्केट से खरीदने और खरीदी का व्यय सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में देने की बात कही। उद्यानिकी कृषकों की फसलों को आवारा मवेशी और जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिये खेत की चेन फेंसिंग अनुदान योजना शुरू करने का सुझाव दिया। भोपाल के समीप सीहोर और रायसेन जिलों के फूलों की खेती करने वाले उद्यानिकी कृषकों ने भोपाल में कार्गो हब बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट के देशों में भारतीय फूलों की अच्छी माँग रहती है। भोपाल में कार्गो हब बनने से फूलों की खेती करने वालों को उनके उत्पाद की अच्छी कीमत मिल सकेगी। उद्यानिकी कृषकों ने जैविक खेती अपनाने में जैविक खेती पंजीयन में होने वाले व्यय को सरकार द्वारा वहन करने का सुझाव दिया। कृषकों ने सोलर सिस्टम के लिये अनुदान देने और प्याज भंडार गृहों के निर्माण के लिए जिलों का टार्गेट बढ़ाने की बात कही। किसानों ने फसल उत्पादन, भंडारण और विपणन के संबंध में अन्य सुझाव भी दिये।

पहली बार व्यवस्था : जांच के दायरे में होंगे बैंक और समितियां, प्रस्ताव शासन को भेजा

मध्यप्रदेश में नियुक्त होगा सहकारी लोकपाल

भोपाल। प्रदेश की साढ़े चार हजार से ज्यादा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई अब स्वतंत्र निकाय करेगा। इसके लिए सहकारी लोकपाल की नियुक्ति होगी। यह ठीक वैसे ही काम करेगा, जैसे अन्य बैंकों के लिए नियुक्त लोकपाल करता है। प्रदेश में पहली बार यह व्यवस्था लागू की जा रही है। सहकारिता आयुक्त कार्यालय ने प्रस्ताव शासन को भेजा है। लोकपाल सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी, सहकारिता विभाग के अपर या संयुक्त पंजीयक स्तर के अधिकारी को बनाया जाएगा।

38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई अब स्वतंत्र निकाय करेगा

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सहकारी समितियों से 50 लाख से ज्यादा किसान जुड़े हैं। हर साल 25 लाख से ज्यादा किसान अल्पावधि कृषि ऋण लेते हैं। इसके लिए सरकार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को 800 करोड़ रूपये से अधिक का ब्याज अनुदान देती हैं। कई समितियों और बैंक की शाखाओं से फर्जी तरीके से किसान के नाम पर ऋण चढ़ाने, राशि जमा होने के बाद भी बकाया बताने सहित अन्य शिकायतें आती हैं।

सामने आ चुके हैं किसानों के नाम पर धोखाधड़ी के मामले : पिछले दिनों ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, छिंदवाड़ा, छतरपुर सहित अन्य बैंकों से जुड़ी शाखाओं में किसानों के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। अभी समितियों के विरुद्ध शिकायतें सहायक पंजीयक, उप पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, अपर पंजीयक के स्तर पर सुनी जाती हैं। इसमें अधिकारियों को बचाने ओर पक्षपात किए जाने की शिकायतें होती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी की स्वतंत्र निकाय की सिफारिश

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने भी शिकायतों के समाधान के लिए स्वतंत्र निकाय गठित करने की सिफारिश की है। इसे देखते हुए सहकारिता आयुक्त कार्यालय ने लोकपाल की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया। संयुक्त पंजीयक अरविंद सिंह सेंगर का कहना है कि प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर होगा।

सामने आ चुके है सौ करोड़ रूपये से अधिक के घोटाले

प्रदेश के राजगढ़, ग्वालियर, शिवपुरी, सागर, उज्जैन, गुना, देवास और छिंदवाड़ा जिला सहकारी बैंक से जुड़ी शाखाओं में सौ करोड़ रूपये से अधिक के घोटाले सामने आ चुके है। इन सभी मामले में किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से ऋण राशि निकाली गई। कर्ज माफी की राशि में भी अनियमितता की गई है।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बच्चों को मिलेगी मदद

भोपाल : एकलव्य शिक्षा विकास योजना' में प्रदेश के वन क्षेत्रों में निवासरत तेन्दूपत्ता संग्राहकों के होनहार बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और उनके शिक्षा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। तेन्दूपत्ता संग्राहक के लिए यह जरूरी है कि पिछले 5 वर्ष में कम से कम तीन वर्षों में न्यूनतम एक मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया हो। फड़ मुंशी और समिति प्रबंधक द्वारा कम से कम तीन वर्षों तक तेन्दूपत्ता सीजन में कार्य करने पर तेंदूपत्ता संग्राहक के बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है।

बच्चों को योजना का लाभ लेने के लिए पिछली वार्षिक परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है। इस सहायता योजना में व्यवसायिक कोर्स के विद्यार्थियों को वार्षिक 50 हजार रूपये दिए जाते हैं । गैर तकनीकी स्नातक विद्यार्थियों को 20 हजार रूपये, कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को 15 हजार रूपये और कक्षा 9वीं एवं 10वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को 12 हजार रूपये की वार्षिक सहायता दी जाती है।

किसानों के हर सुख-दुख में हमेशा साथ रहा हूँ और आगे भी रहूँगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल :आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी है। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन की लागत को कम करना, कृषि उपज के उचित दाम दिलाना और प्राकृतिक आपदा या अन्य स्थिति में उपज को हुए नुकसान में किसान को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देना, राज्य सरकार के प्रयासों में शामिल हैं। इन्हीं प्रयासों के चलते हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देश में फसल क्षति की सबसे बड़ी सहायता राशि का वितरण कर राष्ट्रीय स्तर पर एक नया रिकार्ड बनाया है। किसानों के 49 लाख फसल क्षति के दावों में 7618 करोड़ रूपये की सहायता राशि उनके खातों में सिंगल क्लिक से अंतरित की गई। यह फसल बीमा राशि प्रदेश के प्रभावित किसानों के लिये संजीवनी बनी है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी किसान भाइयों-बहनों के हर सुख-दुख में मैं हमेशा साथ रहा हूँ और साथ रहूँगा। प्राकृतिक आपदा हो या बाढ़, बारिश, ओलावृष्टि, फसलों पर आए संकट में किसानों को कभी भी आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। बीते दिनों हुई ओलावृष्टि और बारिश से फसलों का जो नुकसान हुआ है, उसके लिये भी राहत राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी।

किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिये सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। किसानों को लाभान्वित करने के लिये सरकार द्वारा नवाचारों को भी निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व और मार्गदर्शन में किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये सभी संभव प्रयास किये जायेंगे।

संभागवार दावे और वितरित राशि

भोपाल संभाग के 5 जिलों में 10 लाख 62 हजार 574 दावों में 2 हजार 58 करोड़ 31 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसमें भोपाल जिले में 80 हजार 167 बीमा दावों में 152 करोड़ 02 लाख रुपए, सीहोर में 2 लाख 82 हजार 520 दावों में 761 करोड़ 23 लाख रूपए, रायसेन में एक लाख 48 हजार 072 दावों में 269 करोड़ 80 लाख रुपए, विदिशा में 2 लाख 56 हजार 273 दावों में 493 करोड़ 99 लाख रुपए और राजगढ़ में 2 लाख 95 हजार 542 दावों में 381 करोड़ 27 लाख रुपए की फसल बीमा राशि वितरित की गई।

पीएम फसल बीमा योजना की क्लेम राशि बनी किसानों के लिये संजीवनी

ग्वालियर संभाग के ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिले में फसल बीमा के 2 लाख 37 हजार 499 दावों में 218 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि वितरित की गई। इसमें ग्वालियर में 1645 दावों में एक करोड़ 19 लाख रुपए, दतिया में 32 हजार 605 दावों में 20 करोड़ 80 लाख रुपए, शिवपुरी में 57 हजार 881 दावों में 40 करोड़ 56 लाख रुपए, गुना में 80 हजार 822 दावों में 87 करोड 73 लाख रुपए और अशोकनगर जिले के 64 हजार 546 फसल बीमा दावों में 68 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि वितरित की गई।

इंदौर संभाग के 8 जिलों में 7 लाख 67 हजार 582 बीमा दावों में 922 करोड़ 84 लाख रुपये की राशि किसानों के खाते में अंतरित की गई। इसमें इंदौर के एक लाख 86 हजार 812 बीमा दावों में 380 करोड़ 54 लाख रुपये, झाबुआ में 45 हजार 666 बीमा दावों में 20 करोड़ 49 लाख रुपये, बड़वानी में 43 हजार 726 बीमा दावों में 22 करोड़ 57 लाख रुपये, खरगोन में एक लाख 5 हजार 266 बीमा दावों में 79 करोड़ 79 लाख रुपये, खण्डवा में एक लाख 43 हजार 456 बीमा दावों में 152 करोड़ 9 लाख रुपये, धार में 2 लाख एक हजार 407 बीमा दावों में 232 करोड़ 57 लाख रुपये, बुरहानपुर में 5 हजार 470 बीमा दावों में 5 करोड़ 89 लाख रुपये और अलीराजपुर के 35 हजार 779 बीमा दावों में 8 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।

जबलपुर संभाग के 8 जिलों में एक लाख 87 हजार 342 बीमा दावों में 141 करोड़ 91 लाख रुपये की राशि किसानों के खाते में अंतरित की गई। इसमें जबलपुर के 11 हजार 86 बीमा दावों में 8 करोड़ 87 लाख रुपये, कटनी में 7 हजार 202 बीमा दावों में 7 करोड़ 34 लाख रुपये, नरसिंहपुर में 34 हजार 895 बीमा दावों में 22 करोड़ 37 लाख रुपये, सिवनी में 27 हजार 809 बीमा दावों में 27 करोड़ 33 लाख रुपये, बालाघाट में

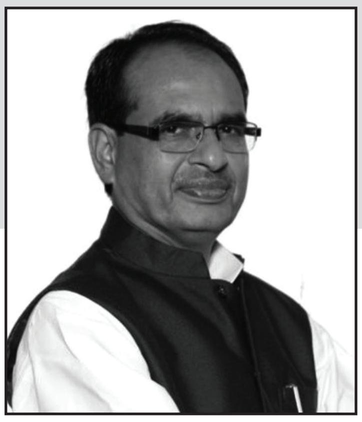

26 हजार 531 बीमा दावों में 22 करोड़ 63 लाख रुपये, छिन्दवाड़ा में 66 हजार 156 बीमा दावों में 44 करोड़ 87 लाख रुपये, डिण्डोरी में 6 हजार 457 बीमा दावों में 3 करोड़ 45 लाख रुपये और मण्डला के 7 हजार 206 बीमा दावों में 5 करोड़ 5 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।

रीवा संभाग के 4 जिलों में 49 हजार 508 दावों में 45 करोड़ 92 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसमें रीवा जिले में 14 हजार 540 बीमा दावों में 16 करोड़ 67 लाख रुपए, सतना में 29 हजार 568 दावों में 22 करोड़ 43 लाख रूपए, सिंगरौली में एक हजार 297 दावों में एक करोड़ 42 लाख रुपए और सीधी में 4 हजार 103 दावों में 5 करोड़ 40 लाख रुपए की फसल बीमा राशि वितरित की गई।

सागर संभाग के 6 जिलों में 3 लाख 729 बीमा दावों में 382 करोड़ 3

फसल क्षति की सबसे बड़ी सहायता राशि का वितरण कर प्रदेश ने बनाया रिकार्ड

लाख रुपये की राशि किसानों के खाते में अंतरित की गई। इसमें सागर के एक लाख 73 हजार 682 बीमा दावों में 265 करोड़ 42 लाख रुपये, निवाड़ी में 8 हजार 62 बीमा दावों में 3 करोड़ 55 लाख रुपये, पन्ना में 11 हजार 237 बीमा दावों में 5 करोड़ 27 लाख रुपये, टीकमगढ़ में 27 हजार 140 बीमा दावों में 14 करोड़ 12 लाख रुपये, छतरपुर में 26 हजार 886 बीमा दावों में 18 करोड़ 62 लाख रुपये और दमोह में 53 हजार 722 बीमा दावों में 75 करोड़ 5 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।

उज्जैन संभाग के 7 जिलों में 19 लाख 22 हजार 528 बीमा दावों में 2867 करोड़ 17 लाख रुपये की राशि किसानों के खाते में अंतरित की गई। इसमें उज्जैन के 5 लाख 93 हजार 831 बीमा दावों में 689 करोड़ 46 लाख रुपये, देवास में 3 लाख 15 हजार 423 बीमा दावों में 666 करोड़ 69 लाख रुपये, नीमच में एक लाख 37 हजार 650 बीमा दावों में 156 करोड़ 18 लाख रुपये, आगर-मालवा में एक लाख 9 हजार 544 बीमा दावों में 182 करोड़ 56 लाख रुपये, रतलाम में 2 लाख 48 हजार 681 बीमा दावों में 318 करोड़ 20 लाख रुपये, मंदसौर में 2 लाख 90 हजार 867 बीमा दावों में 368 करोड़ 95 लाख रुपये और शाजापुर में 2 लाख 26 हजार 532 बीमा दावों में 485 करोड़ 13 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।

नर्मदापुरम् संभाग के 3 जिलों में 4 लाख 3 हजार 944 दावों में 925 करोड़ 21 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसमें नर्मदापुरम् (होशंगाबाद) जिले में एक लाख 49 हजार 614 बीमा दावों में 273 करोड़ 20 लाख रुपए, हरदा में एक लाख 25 हजार 856 दावों में 345 करोड़ 79 लाख रूपए और बैतूल में एक लाख 28 हजार 474 दावों में 306 करोड़ 79 लाख रुपए की फसल बीमा राशि वितरित की गई।

चम्बल संभाग के 3 जिलों में 20 हजार 357 दावों में 25 करोड़ 37 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसमें श्योपुर जिले में 14 हजार 526 बीमा दावों में 21 करोड़ 76 लाख रुपए, मुरैना में 4 हजार 346 दावों में 2 करोड़ 44 लाख रूपए और भिण्ड में एक हजार 485 दावों में एक करोड़ 17 लाख रुपए की फसल बीमा राशि वितरित की गई।

शहडोल संभाग के 3 जिलों में 32 हजार 961 दावों में 30 करोड़ 93 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसमें अनूपपुर जिले में 7 हजार 236 बीमा दावों में 7 करोड़ 78 लाख रुपए, उमरिया में 9 हजार 941 दावों में 8 करोड़ 26 लाख रूपए और शहडोल में 15 हजार 784 दावों में 14 करोड़ 89 लाख रुपए की फसल बीमा राशि अंतरित की गई।

भोपाल-नर्मदापुरम संभाग के लिये अब तक करीब 1255 करोड़ की जल-प्रदाय योजनाएँ मंजूर

जल जीवन मिशन में 2 हजार 279 जल संरचनाओं के कार्य जारी

भोपाल : प्रदेश की ग्रामीण आबादी को उनके घर में ही पेयजल उपलब्ध करवाने के प्रयास तेजी से जारी है। जहाँ जलस्त्रोत हैं, वहाँ उनका समुचित उपयोग कर आसपास के ग्रामीण रहवासियों को पेयजल प्रदाय किया जायेगा। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्त्रोत नहीं हैं वहाँ यह निर्मित किए जायेंगे। कोई भी ग्रामीण रहवासी पेयजल के लिए परेशान नहीं हो यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम द्वारा भोपाल-नर्मदापुरम संभाग के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल जिले में अब तक एक हजार 254 करोड़ 70 लाख 17 हजार रूपये लागत की 2279 जल-प्रदाय योजनाओं पर विभाग के मैदानी अमले द्वारा जल जीवन मिशन के मापदण्डों के अनुसार कार्य प्रारंभ किये गये हैं। दोनों संभाग के 987 ग्रामों में शत-प्रतिशत परिवारों को नल कनेक्शन से जल पहुँचाया जा चुका हैं। इसमें भोपाल संभाग के 639 और नर्मदापुरम संभाग के 348 गांव शामिल हैं।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में प्रदेश की समग्र ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति किए जाने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम द्वारा जल संरचनाओं की स्थापना एवं विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं। इनमें भोपाल जिले की 170, विदिशा 297, रायसेन 264, सीहोर 231, राजगढ़ 145, नर्मदापुरम 423, हरदा 252 और बैतूल जिले की 497 जलसंरचनायें शामिल हैं। इन जिलों के विभिन्न ग्रामों में पूर्व से निर्मित पेयजल अधो-संरचनाओं को नये सिरे से तैयार कर रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत भी कार्य किए जा रहे हैं।

एग्री बिजनेस अपनाकर नौकरी मांगने वाले नहीं देने वाले बनें युवा - केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर

अंचल के युवा सेंटर की मदद से गढ़ेंगे भारत का सुनहरा भविष्य

"सेंटर फॉर एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप" का लोकार्पण

भोपाल : ग्वालियर एवं चंबल क्षेत्र के किसानों एवं कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक युवाओं को बड़ी सौगात मिली है। केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में "सेंटर फॉर एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप" के नव-निर्मित भवन का लोकार्पण किया। श्री तोमर ने कहा कि सेंटर की मदद से ग्वालियर-चंबल अंचल के नौजवान कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू कर भारत का सुनहरा भविष्य गढ़ेंगे। नए-नए स्टार्टअप खड़े होने से आत्म-निर्भर भारत की नींव और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का यह प्रयास है कि युवा नौकरी मांगने के बजाय एग्री बिजनिस से जुड़कर दूसरों को नौकरी देने वाले बनें। इसी उद्देश्य से इस प्रकार के सेंटर खोले जा रहे हैं।

नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) के सहयोग से 7 करोड़ रूपए से अधिक लागत से ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े कृषि महाविद्यालय परिसर में "सेंटर फॉर एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप" के लिए भवन का निर्माण किया गया है। आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से सुसज्जित इस सेंटर को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य अगले चार वर्षों में 100 से अधिक स्टार्टअप खड़े करना है। साथ ही कृषि एवं उससे जुड़ी विभिन्न प्रकार की 240 आर्थिक गतिविधियों के लिए क्षेत्रीय किसानों एवं युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण तथा आर्थिक एवं तकनीकी मदद मिलेगी। इस सेंटर के माध्यम से फसल उत्पादन, फसल सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित 130 प्रकार की तकनीक भी विकसित कर लोगों को जागरूक करने का काम होगा।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर सरकार द्वारा एग्री बिजनेस स्टार्टअप, फूड प्रोसेसिंग और नवाचारों के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद दी जा रही है। साथ ही एफपीओ (कृषक उत्पादक संगठन) और एग्री स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बोनी से लेकर उपज को बाजार में अच्छे दाम दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ किसानों की मदद में जुटी है। श्री तोमर ने जानकारी दी कि इस साल समर्थन मूल्य पर सरकार ने पिछले साल के मुकाबले दोगुनी खरीदी की है। गेहूँ और धान के साथ सरकार दलहन, तिलहन एवं अन्य मोटे अनाज भी समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। श्री तोमर ने आह्वान किया कि किसान पारंपरिक खेती के साथ सब्जी और फूलों की खेती भी करें, जिससे उनकी आय दोगुनी हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि अधो-संरचना के लिए एक लाख करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। देश की आजादी के बाद पहली बार गाँवों के समीप खेती से संबंधित साधन उपलब्ध कराने के लिये डेढ़ लाख करोड़ रूपए की राशि की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है।

नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. जी.आर. चिंतला ने कहा कि नई पीढ़ी कृषि क्षेत्र से बाहर न जाकर नई तकनीक और ऊर्जा के साथ कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाए, इसके लिए नाबार्ड द्वारा कारगर कदम उठाए गए हैं। कृषि उद्यम से जुड़ने के इच्छुक युवाओं और किसानों की समस्याओं के समाधान में नाबार्ड-एबिक अहम रोल अदा कर रहा है। देश में नाबार्ड द्वारा आधा दर्जन एबिक की स्थापना की जा चुकी है। इसी कड़ी में ग्वालियर में यह सातवाँ सेंटर स्थापित किया गया है। सेंटर के जरिए खेती एवं किसानों के स्टार्टअप, तकनीकी विकास, नेटवर्किंग, वित्तीय सहायता, व्यवसाय शुरू करने के लिये मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, शोध और कानूनी पहलुओं के विषय में मदद मुहैया कराई जायेगी।

प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। श्री पटेल ने कहा कि इस सेंटर के रूप में नाबार्ड और भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के किसानों को एक बड़ा उपहार मिला है। उन्होंने कहा कि सेंटर से प्रदेश में प्र-संस्करण और एग्रीटेक से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। श्री पटेल ने कहा प्रदेश सरकार की स्पष्ट नीति और मिशन है कि कृषि विविधीकरण के साथ प्र-संस्करण को भी बढ़ावा मिले।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि किसानों को अपनी आय दोगुनी करने के लिये खाद्य प्र-संस्करण से भी जुड़ना होगा। इस दिशा में ग्वालियर का यह सेंटर मील का पत्थर साबित होगा। मध्यप्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण की अपार संभावनाएँ हैं।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एस.के. राव ने कहा कि विश्वविद्यालय सेंटर की सफलता में महती भूमिका निभायेगा। मध्यप्रदेश नाबार्ड के प्रबंधक श्री निरूपम मेहरोत्रा और सीजेएम श्री देवाशीष पाढ़ी ने भी संबोधित किया।

राज्य स्तरीय प्रदर्शनी एवं ईको फेस्ट का भी किया शुभारंभ

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर सहित अन्य अतिथियों ने राज्य स्तरीय प्रदर्शनी "उमंग-2022" और ईको फेस्ट का भी शुभारंभ किया। कृषि व्यवसाय केन्द्र द्वारा इको फैक्टरी फाउंडेशन के साथ कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये एमओयू भी किया गया। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने नाबार्ड द्वारा किसानों एवं स्व-सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री और बाजार मुहैया कराने के लिये तैयार किए गए चलित रूरल मार्ट वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

ई-केवायसी से होगी 5 करोड़ खाद्यान्न हितग्राही की पहचान - प्रमुख सचिव खाद्य श्री किदवई

भोपाल : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में 4 करोड़ 94 लाख पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह रियायती दर पर खाद्यान्ध एवं अन्य सामग्री का वितरण उचित मूल्यय दुकानों के माध्यमम से किया जा रहा है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिये विभाग द्वारा ई-केवायसी का अभियान चलाया जा रहा है। इससे जहाँ एक ओर हितग्राही अपने डाटा में हुई त्रुटियों में सुधार करवा सकेंगे, वहीं दूसरी ओर अपात्र हितग्राहियों की पहचान भी की जा सकेगी।

श्री किदवई ने बताया कि अभियान में ई-केवायसी द्वारा पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस एवं आधार-डाटाबेस में दर्ज नाम, पता, लिंग एवं आयु के आधार पर मिलान किया जाता है। जिन हितग्राहियों के डाटाबेस का मिलान होता है उनके ई-केवायसी जेएसओ लॉगिन से अनुमोदित किये जाते हैं।

24 हजार 952 उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध है ई-केवायसी सुविधा

श्री किदवई ने बताया कि प्रदेश की लगभग 24 हजार 952 उचित मूल्य दुकान पर पात्र हितग्राहियों के लिये ई-केवायसी कराने की सुविधा उपलब्धा कराई गई है। हितग्राही अपने आधार नंबर के माध्यम से उचित मूल्यी दुकान पर ई-केवायसी करा रहे हैं। शारीरिक रूप से अक्षम एवं वृद्ध हितग्राही की ई-केवायसी, विक्रेता द्वारा घर पर जाकर की जा रही है।

25 प्रतिशत हितग्राहियों का हुआ ई-केवायसी

श्री किदवई ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 2 लाख हितग्राही के ई-केवायसी कराये जा रहे है। अभी तक एक करोड़ 4 लाख 53 हजार 675 हितग्राही के ई-केवायसी किये जा चुके हैं। इस प्रक्रिया से वास्तविक हितग्राही बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर सुगमता से राशन सामग्री प्राप्तं कर सकेंगे। हितग्राही वन नेशन-वन राशनकार्ड योजना के तहत किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे।

404.37 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जन के साथ प्रदेश के लाजवाब 4 साल - खाद्य मंत्री श्री सिंह

2020-21 में प्रदेश बना देश का सर्वोच्च गेहूँ उपार्जक

भोपाल : किसानों से समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन के लिये प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार ने गेहूँ उपार्जन के साथ धान, ज्वार एवं बाजरे की खरीदी की। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि विगत 4 वर्षों में 73 लाख 29 हजार किसानों से 535.28 लाख मीट्रिक टन गेहूँ एवं धान की खरीदी की गई। इसमें वर्ष 2020-21 में 15 लाख 94 हजार किसानों से 129.42 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जित कर प्रदेश देश में सर्वोच्च गेहूँ उपार्जन के साथ प्रथम स्थान पर रहा। मंत्री श्री सिंह ने बताया कि मोटे अनाज के रूप में ज्वार एवं बाजरे की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई। इसमें 17 हजार 868 किसानों से 73 हजार 902 लाख मीट्रिक टन ज्वार एवं 47 हजार 108 किसानों से 2 लाख 2 हजार 355 मीट्रिक टन बाजरे का उपार्जन किया गया।

मंत्री श्री सिंह ने बताया कि किसानों से उनकी फसल के उपार्जन की प्रक्रिया पारदर्शी एवं सरल बनाई गई है। यह प्रक्रिया समर्थन मूल्य पर किसान पंजीयन से प्रारंभ होती है। किसानों की सुविधा एवं पंजीयन के विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराने की दृष्टि से किसान पंजीयन सहकारी समिति के अतिरिक्त महिला स्व-सहायता समूह, कृषि उत्पादक संगठनों, एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायतों के स्तर पर स्थापित सुविधा केन्द्रों के साथ-साथ साइबर कैफे पर भी किसान पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

भुगतान की व्यवस्था ई-बैंकिंग से

मंत्री श्री सिंह ने बताया कि समर्थन मूल्य पर उपार्जित फसल की राशि का भुगतान ई-बैंकिंग के माध्यम से किया गया। इसमें विगत 4 वर्षों में गेहूँ एवं धान की खरीदी के विरुद्ध किसानों को 98441.25 करोड़ रुपये एवं ज्वार एवं बाजरा के उपार्जन के भुगतान स्वरूप 64 हजार 976 किसानों को 711.672 करोड़ की राशि किसान के बैंक खाते में सीधे अंतरित की गई। इससे किसानों को राशि प्राप्त करने की समितियों पर निर्भरता समाप्त हो गई है। किसानों के पंजीयन में बैंक खाते की प्रविष्टि में त्रुटि के कारण भुगतान में आ रही समस्या के निराकरण हेतु आधार से लिंक बैंक खाते में भुगतान की व्यवस्था की जा रही है, जिसके अतिरिक्त समितियों के कमीशन, प्रासंगिक व्यय, परिवहन व्यय, हेण्डलिंग व्यय आदि का भी ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है।

वास्तविक किसान से खरीदी की सुनिश्चितता

मंत्री श्री सिंह ने बताया कि उपार्जन में वास्तविक कृषकों से ही उपज की खरीदी सुनिश्चित करने के लिये किसान की फसल एवं बोये गये रकबे की जानकारी राजस्व विभाग के गिरदावरी डाटाबेस से ली जाती है। पंजीकृत किसानों में से दो हेक्टेयर से अधिक रकबे, सिकमी/बटाईदारी/वनपट्टाधारी/ विगत वर्ष के पंजीयन से 50 प्रतिशत से अधिक रकबा एवं आधार डाटाबेस तथा पंजीयन में नाम में भिन्नता वाले किसानों के रकबे एवं फसल के सत्यापन की व्यवस्था की गई है, ताकि बिचौलियों को उपार्जन व्यवस्था से बाहर किया जा सके।

किसानों के हित में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की व्यवस्था

मंत्री श्री सिंह ने बताया कि किसानों को पंजीयन, समर्थन मूल्य पर उपज के विक्रय, बारदाना, गुणवत्ता, केन्द्र संचालन एवं भुगतान में किसी प्रकार समस्या होने पर शिकायत के लिये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181, राज्य एवं जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष में शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसकी सतत् मॉनीटरिंग कर निराकरण किया जाता है।

भोपाल को–ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक के पहले क्यूआर कोड का शुभारंभ

भोपाल। बबलू सातनकर उपायुक्त सहकारिता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी रघुनाथ प्रसाद हजारी द्वारा भोपाल को–ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक का प्रथम क्यूआर कोड का शुभारंभ किया गया। निकट भविष्य में बैंक के द्वारा अपने सभी ग्राहकों व जिले के व्यवसाईयों को बैंक से जोड़ने में सहायक व लाभकारी होगा।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने बारंगा से किया "मेरा गाँव-मेरा तीर्थ अभियान" का शुभारंभ

भोपाल : किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने गाँव के सर्वांगीण विकास के लिये "मेरा गाँव-मेरा तीर्थ अभियान" का शुभारंभ बारंगा से किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान में गाँव को समस्या रहित बनाने का संकल्प लिया जाएगा। सभी ग्रामीण संकल्प लेंगे कि गाँव को स्वच्छ और समस्या रहित कर आदर्श एवं तीर्थ के रूप में विकसित किया जाये।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि अभियान में गाँव को स्वच्छ रखने, गौवंश की सुरक्षा करने, गाँव को नशामुक्त करने, गाँव में एकता बनाएँ रखने, सामाजिक समरसता को कायम रखने के लिए ग्रामीणों को संकल्प दिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को प्राकृतिक और जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प और मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे को चरित्रार्थ करते हुए अपने गाँव को आदर्श बनाकर तीर्थ के रूप में विकसित करना है।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि हम हर गाँव को आदर्श बनाएंगे, हर गाँव को तीर्थ बनाएंगे, जिससे सब सुखी, सम्पन्न और समृद्धशाली बनें। हमारा समन्वित प्रयास होगा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने के आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश और प्रधानमंत्री के आत्म-निर्भर भारत के सपने को साकार कर सकें।

डेढ़ दशक में उद्यानिकी फसलों के रकबे और उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि

भोपाल : मध्यप्रदेश में पिछले डेढ़ दशक में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल में 5 गुना और उत्पादन में 7 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2006 में उद्यानिकी फसलों का कुल रकबा 4 लाख 69 हजार हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 23 लाख 43 हजार हेक्टेयर हो गया। उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि होने का सीधा प्रभाव उत्पादन में हुई वृद्धि में भी दिखाई देता है। इस अवधि में उद्यानिकी फसलों का उत्पादन भी 42 लाख 98 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर अब सात गुना से अधिक 340 लाख 31 हजार मीट्रिक टन हो गया है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सुविचारित नीतियों और दूरदर्शिता से उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन में हुई इस उल्लेखनीय वृद्धि का ही परिणाम है कि मध्यप्रदेश मसाला, सब्जी, फल और फूल उत्पादन में देश के पहले 5 राज्यों में शामिल है। प्रदेश मसाला फसलों के उत्पादन में देश में पहले, सब्जी में तीसरे, फूल में चौथे और फल उत्पादन में पाँचवें स्थान पर है।

प्रदेश में वर्ष 2006 का फलों की खेती का रकबा 46 हजार 777 हेक्टेयर से बढ़कर 4 लाख 5 हजार हेक्टेयर और उत्पादन 11 लाख 73 हजार मीट्रिक टन से 82 लाख 44 हजार मीट्रिक टन बढ़ा है। इस अवधि में सब्जी का क्षेत्र एक लाख 96 हजार हेक्टेयर और उत्पादन 27 लाख 97 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर क्षेत्र 10 लाख 40 हजार हेक्टेयर और उत्पादन 206 लाख 31 हजार मीट्रिक टन हो गया। मसाला फसलों का क्षेत्र भी 2 लाख 7 हजार 563 हेक्टेयर और उत्पादन 2 लाख 33 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 82 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 46 लाख 37 हजार मीट्रिक टन हो गया। फूलों की खेती जो वर्ष 2006 में मात्र 3 हजार 667 हेक्टेयर में होती थी, वह 35 हजार 554 हेक्टेयर में हो रही है।

प्रदेश में औषधीय एवं सुगंधित फूलों की खेती जो मात्र 15 हजार 650 हेक्टेयर में होती थी, अब 42 हजार 956 हेक्टेयर में हो रही है।

वर्ष 2018 के उद्यानिकी की राष्ट्रीय सांख्यिकी में मध्यप्रदेश ने देश के कुल 8123.87 हजार मीट्रिक टन मसाला उत्पादन में 1191.81 हजार मीट्रिक टन का योगदान किया है। यह देश के सकल मसाला उत्पादन का 14.67 प्रतिशत है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में देश के कुल 184394.51 हजार मीट्रिक टन उत्पादन में मध्यप्रदेश ने 17545.48 हजार मीट्रिक टन सब्जी का योगदान कर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाद तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस तरह देश के सब्जी उत्पादन में मध्यप्रदेश का योगदान 9.52 प्रतिशत रहा।

प्रदेश फूलों के उत्पादन में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बाद देश में चौथे स्थान पर है। देश के फूल उत्पादन में प्रदेश का हिस्सा 10.15 प्रतिशत है। देश के कुल 97357.51 हजार मीट्रिक टन फल उत्पादन में 7416.91 हजार मीट्रिक टन योगदान कर मध्यप्रदेश आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात के बाद पाँचवें स्थान पर है। इस तरह फलों के उत्पादन में प्रदेश का देश के उत्पादन में 7.62 प्रतिशत हिस्सा है।

पिछले डेढ़ दशक में प्रदेश में उद्यानिकी फसल उत्पादों के भण्डारण के लिये बढ़ी संख्या में कोल्ड-स्टोरेज और भण्डार-गृह बनाये गये हैं। वर्ष 2008 में प्रदेश में करीब एक लाख 19 हजार मीट्रिक टन क्षमता के 2,890 प्याज भण्डार-गृह थे, जो अब 3 लाख 79 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा क्षमता के 8,530 भण्डार गृह हो गये हैं।

खण्डवा जिले के जैविक परिवार ब्रांड ने बाजार में पहुँच बनाई

भोपाल : जैविक खेती से स्वस्थ भारत बनाने का मिशन लेकर चल रहे खंडवा जिले के 500 छोटे किसानों ने पूरे देश का ध्यान आकृष्ट किया है। ये किसान 918 हेक्टेयर में जैविक उत्पाद ले रहे हैं। इनके उत्पादों का "जैविक परिवार" ब्रांड हर घर पहुँच रहा है। सतपुड़ा जैविक प्रोडयूसर कंपनी से जुड़े किसान चाहते हैं कि देश के नागरिकों को शुद्ध अनाज, फल-सब्जी मिले। वे दवाओं से दूर रहे और हमारी धरती विषमुक्त रहे।

कंपनी से जुड़े झिरन्या तहसील के बोदरानिया गाँव के दारा सिंह धार्वे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सोच से पूरी तरह सहमत हैं कि जैविक खेती धरती और मनुष्य को बचाने का सबसे ठोस उपाय है। दारा सिंह धार्वे को जैविक गेहूँ के अच्छे दाम मिल रहे हैं। इस साल 2500 रूपये प्रति क्विंटल तक मिल जायेंगे। वे कहते हैं - "जैविक खेती से अब ज्यादा से ज्यादा किसान जुड़ना चाहते हैं। रासायनिक खाद से खेती की लागत भी बढ़ जाती है और स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है।

कंपनी के सीईओ श्री विशाल शुक्ला बताते हैं कि कंपनी को बने तीसरा साल चल रहा है। इतने कम समय में कंपनी के जैविक उत्पादों ने मार्केट में अच्छी पहचान बना ली है। "जैविक परिवार" ब्रांड के कारण खेत और उपभोक्ता के बीज मजबूत संबंध बन गया है। वे बताते हैं कि अगले तीन सालों में 65 शहरों में सवा 3 लाख जैविक उत्पादों के उपभोक्ता जुड़ जायेंगे। जोमेटो, स्वीगी, निंबस, ई-कार्ट, मीशो, गाट इट जैसे डिलीवरी पार्टनर्स हमसे जुड़ गये हैं और इंदौर में काम भी शुरू कर दिया गया है। इस प्रकार आधुनिक मार्केटिंग और टेक्नालाजी की मदद से जैविक उत्पादों की पहुँच बढ़ाने की कोशिशें जारी है। "जैविक परिवार" को वितरक मिल रहे हैं। इसलिये ग्राहक सेवा विभाग हमने खोला है और उनके संपर्क में सेल्स टीम रहती है।

श्री शुक्ला कहते हैं कि - "किसान उत्पाद संगठनों को एक साथ लाकर खेती के क्षेत्र में आर्थिक उद्यमिता की शुरूआत करने का जो सपना मुख्यमंत्री जी ने देखा है उसे साकार करने में हम हमेशा आगे रहेंगे।" वे कहते हैं - "कि मुख्यमंत्री की सोच प्रगतिशील है। वे दूरदृष्टा की तरह सोचते हैं।"

सतपुड़ा जैविक प्रोड्यूसर कंपनी अस्तित्व में आने के संबंध में श्री शुक्ला बताते हैं कि- "शुरूआत गाँव-गाँव जाकर चौपाल बैठकें करने से हुई। छोटी-छोटी खेती करने वाले किसानों को एकजुट करना जरूरी था। एक साथ मिल कर खेती करने और मार्केटिंग करने के फायदों पर चर्चाओं के दौर शुरू हुए। शुरूआत दस किसानों से हुई। शुरूआत में गेहूँ, सोयाबीन और प्याज के लिए आपस में समूह बनाये। इन समूहों से मिलकर समितियाँ बनीं और इस तरह धीरे-धीरे किसान जुड़ते गये और यह सिलसिला जारी है। इसी बीच कोरोना काल आ गया लेकिन किसानों को परेशानी नहीं हुई। गेहूँ की खरीदी जारी रही। उनका जैविक उत्पाद सब्जी सीधे ग्राहकों के घर पहुँचने लगा।

कंपनी से जुड़ने का कारण बताते हुए सिंगोट गांव के किसान श्री राजेश टिरोले कहते हैं कि - "एक साथ मिलकर एक ब्रांड के नाम से उत्पाद मार्केट में आने से दाम बढ़ते हैं और सभी किसानों को फायदा होता है।" श्री राजेश दो हेक्टेयर के छोटे किसान हैं। वे गेहूँ और सब्जियाँ लगाते हैं। शुद्ध रूप से जैविक खाद का उपयोग करते हैं। वे बताते हैं कि - "कंपनी में जुड़ने से जैविक सब्जियों के अच्छे दाम मिलने लगे हैं। पहले बहुत कम दाम में सब्जियाँ बिकती थी। अब जैविक परिवार ब्रांड के माध्यम से अच्छे दाम घर बैठे मिल रहे हैं। कंपनी के कारण हमारा सीधे ग्राहक से वास्ता पड़ा है। हमें अपना रेट तय करने की छूट है। कंपनी के जरिए पूरा माल बिक जाता है और हमें अपनी मेहनत का दाम मिल जाता है।"

पुनासा तहसील के राजपुरागांव में श्री मनोज पांडे तीन एकड़ में जैविक पद्धति से गेहूँ और सब्जियाँ उगा रहे हैं।

(पृष्ठ 1 का शेष)

इंदौर मॉडल शहरों को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त....

मैं दिल्ली से इंदौर के सफाईकर्मियों को प्रणाम एवं नमन करता हूँ।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि आने वाले 2 वर्षों में देश के 75 बड़े नगरीय निकायों में इस प्रकार के गोबर-धन बायो सीएनजी प्लांट बनाने पर काम किया जा रहा है। यह अभियान भारत के शहरों को स्वच्छ बनाने, प्रदूषण रहित बनाने, क्लीन एनर्जी की दिशा में बहुत मदद करेगा। अब तो शहरों में ही नहीं बल्कि देश के गाँव में भी हजारों की संख्या में गोबर-धन बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनसे हमारे पशुपालकों को गोबर से भी अतिरिक्त आय मिलनी शुरू हुई है। हमारे गाँव देहात में किसानों को बेसहारा जानवरों से जो दिक्कत होती है, वह भी इस तरह के गोबर-धन प्लांट होने से कम हो जाएगी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इंदौर के प्लांट से सीएनजी तो मिलेगी ही इसके अलावा 100 टन जैविक खाद भी यहाँ से रोजाना निकलेगा। सीएनजी से प्रदूषण कम होगा और हर व्यक्ति को जीवन जीने में उसकी सुविधा बढ़ेगी। इससे इंदौर शहर में हर रोज करीब-करीब 400 बसें चलाई जा सकेंगी। इस प्लांट से सैकड़ों युवाओं को किसी न किसी रूप में रोजगार भी मिलने वाला है। यानी यह ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने में भी मददगार होगा। प्लांट से जो जैविक खाद बनेगी उससे हमारी धरती माँ को भी नया जीवन मिलेगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि किसी भी चुनौती से निपटने के 2 तरीके होते हैं, पहला तरीका है कि उस चुनौती का तत्कालीन समाधान कर दिया जाए। दूसरा तरीका यह होता है कि उस चुनौती से ऐसे निपटा जाए कि सभी को स्थाई समाधान मिले। बीते 7 वर्षों में हमारी सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, वह योजनाएँ स्थाई समाधान देने वाली हैं और एक साथ कई लक्ष्य को साधने वाली होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को ही लीजिए, इससे स्वच्छता के साथ महिलाओं की गरिमा, बीमारियों से बचाव, गाँव-शहरों को सुंदर बनाने, रोजगार के अवसर तैयार करने जैसे अनेक काम एक साथ हुए हैं। अब हमारा फोकस घर से और गली से निकले कचरे के निस्तारण का है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आज देशभर के शहरों में लाखों टन कूड़ा ऐसे ही हजारों एकड़ जमीन को घेरे हुए हैं। ये शहरों के लिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की भी बड़ी वजह है। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में इस समस्या से निपटने के लिए काम किया जा रहा है। आने वाले 2 या 3 वर्षों में कूड़े के इन पहाड़ों से हमारे शहरों को मुक्ति मिल सके, उन्हें ग्रीन जोन में बदला जा सके, इसके लिए राज्य सरकारों को हर संभव मदद दी जा रही है। यह भी अच्छी बात है कि इस साल 2014 की तुलना में अब देश में शहरी कूड़े के निस्तारण की क्षमता 4 गुना तक बढ़ चुकी है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के लिए 1600 से अधिक निकायों में मटेरियल रिकवरी पेसिफिक फेसिलिटी भी तैयार की जा रही है। इस तरह की आधुनिक व्यवस्थाएँ भारत के शहरों में सर्कुलर इकोनामी को भी एक नई शक्ति दे रही है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा इससे नई अर्थ-व्यवस्था जन्म लेगी। इंदौर ने यह सब कर दिखाया है। आज भी देश-विदेश से लोग यह देखने आते हैं कि इंदौर में स्वच्छता एवं सफाई के लिए कैसे कार्य हुआ है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कोयले के कारखानों में पराली के उपयोग से किसानों को अतिरिक्त आय होगी। भारत में सौर ऊर्जा को भी अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत विश्व के प्रथम पाँच देशों में शामिल हो गया है। अब किसान भी सौर ऊर्जा बनाएंगे। किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता भी बनेंगे। तकनीकी, नवाचार एवं परिश्रम से हम ग्रीन एवं क्लीन फ्यूचर सुनिश्चित करेंगे।

"सर्कुलर इकोनामी" तथा "वेस्ट टू वेल्थ" के सिद्धांतों के अनुरूप है इंदौर का प्लांट -केंद्रीय मंत्री श्री पुरी

केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि "आज से चार वर्ष पहले जब मैं इंदौर में एक कॉन्फ्रेंस के लिए आया था तब जापान से शामिल हुए मंत्री से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि इंदौर शहर में उन्होंने बहुत कुछ देखा पर कचरा नहीं देखा। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार 5 वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम आकर इंदौर ने देश में कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि इंदौर देश का पहला शहर था, जिसे वाटर प्लस स्टेटस प्रमाणित किया गया। इंदौर की शानदार सफलता का श्रेय प्रदेश की सरकार को जाता है। प्रदेश के अन्य शहर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, सिंगरोली, बुरहानपुर और राजगढ़ ने भी स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा वेस्ट-टू-वेल्थ के सिद्धांत पर जोर दिया जाता रहा है, इसलिए इंदौर का यह बायो सीएनजी प्लांट हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इंदौर गार्बेज मुक्त शहर और सस्टेनेबल विकास की दिशा में एक नई मिसाल कायम करने जा रहा है।

इंदौर के प्रयास सबसे अलग

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इंदौर देश का पहला वॉटर प्लस शहर है। यहाँ डस्ट फ्री शहर, इंदौर बिन फ्री के साथ जीरो वेस्ट कॉलोनी, जीरो वेस्ट इवेंट, जीरो वेस्ट मार्केट और जीरो वेस्ट वार्ड विकसित किए जा रहे हैं। इंदौर शहर के 21 बाजार जीरो वेस्ट मार्केट घोषित हुए हैं, जहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि इंदौर में झोलाधारी इंदौरी अभियान का आगाज भी किया गया है। उन्होंने कहा कि इंदौर नगरीय क्षेत्र की स्लम बस्तियों को ग्रीन स्लम के रूप में विकसित करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। सरस्वती एवं कान्ह रिवर लाइफ लाइन प्रोजेक्ट नदियों के पुनर्जीवन के आंदोलन का प्रतीक है। इंदौर शहर के पुराने कचरे के पहाड़ों को वैज्ञानिक पद्धति से समाप्त किया गया है। भोपाल सहित अन्य शहरों में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पंचामृत का मंत्र दिया है। इस मंत्र के अनुरूप मध्यप्रदेश में सोलर एनर्जी और बायोमास के उपयोग को भी आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण परियोजनाओं का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के अपनी तरह के अनोखे गोबर धन सीएनजी संयंत्र के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी सहित सभी वर्चुअली और एक्चुअली उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की प्रेरणा से इंदौर ने 'वेस्ट-टू-वेल्थ' के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। हमें गर्व है कि गीले कचरे से सीएनजी बनाने वाले इस एशिया के सबसे बड़े गोबर-धन प्लांट का आज प्रधानमंत्री जी वर्चुअल लोकार्पण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़े विषयों पर पूरी दुनिया को दिशा दी है। प्रधानमंत्री जी के लिए विश्व के अन्य देशों के प्रमुख वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड और वन नरेन्द्र मोदी जैसी प्रशंसनीय उक्ति का प्रयोग करते हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूरे संसार के कल्याण की बात को ग्लोबल गुड, पी-3 एप्रोच, मिशन लाइफ, वेस्ट-टू-वेल्थ और पंचामृत के माध्यम से सामने रखा है।

प्रधानमंत्री जी के इस पर्यावरण हितैषी मंत्र और संकल्प को पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश ने अमल प्रारंभ किया है। मध्यप्रदेश उनके इस मंत्र को धरती पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव भारत की प्रगति के लिए केवल अमृत महोत्सव नहीं बल्कि स्वर्ण काल है। मध्यप्रदेश स्वच्छता और पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर दिखाएगा।

पशुपालकों और किसानों से खरीदेंगे गोबर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह प्लांट इंदौर के आसपास के ग्राम से पशुपालकों और किसानों से गोबर और अन्य कचरे को क्रय कर धन बनाने वाला संयंत्र होगा। अनेक परिवारों को इस प्लांट से स्थायी रोजगार मिल रहा है। कचरे के साथ गोबर का उपयोग बैक्टीरिया डेवलप करने की प्रोसेसिंग में किया जाएगा। इंदौर में बाजार मूल्य से 5 रूपए प्रति किलो कम कीमत पर सिटी बसों के लिए सीएनजी की उपलब्धता होगी। प्लांट में शुरूआती दौर में 21 प्रतिशत और अगले तीन वर्ष में शत-प्रतिशत सौर ऊर्जा का उपयोग होगा। इंदौर शहर को कार्बन क्रेडिट का लाभ मिलेगा। साथ ही इस प्लांट से आगामी 20 वर्ष तक इंदौर नगर निगम को प्रति वर्ष 2 करोड़ 52 लाख प्रीमियम मिलता रहेगा।

क्लाइमेट स्मार्ट विलेज योजना से किसानों की लागत हुई कम और मुनाफा हुआ ज्यादा

भोपाल : फसलों तक पानी पहुँचा, सिंचाई की समस्या दूर हुई, मुफ्त उन्नत बीज मिले, खेतों में लाइनिंग फार्म पोंड बने और कृषि अधिकारियों के मार्गदर्शन से राजगढ़ के किसानों की खेती-किसानी की राह आसान हुई। "क्लाइमेट स्मार्ट विलेज योजना" में राजगढ़ के श्री जसमाल सिंह, श्री शंकर सिंह और श्री मांगीलाल की खेती से जुड़ी दिक्कतें कृषि अधिकारियों से मिली सलाह से दूर हो गईं। अब वे यूरिया और अन्य खाद का संतुलित मात्रा में प्रयोग कर ब्रॉड बेड फरो विधि से ज्यादा उत्पादन लेते हैं।

राजगढ़ जिले के ग्राम फतेहपुर के भील कृषक श्री जसमाल सिंह के पास 0.519 हेक्टेयर कृषि भूमि है। पहले वे मक्का की फसल देशी बीज छिड़काव विधि से बोते थे। बीज के अधिक मात्रा में उपयोग से खर्च अधिक और लाभ कम होता था। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज परियोजना में श्री जसमाल ने मक्का की बोनी में लीफ कलर चार्ट के अनुसार यूरिया की संतुलित मात्रा का उपयोग किया, जिससे यूरिया की काफी बचत हुई। ब्रॉड बेड फरो विधि से मक्का की बोनी से सूखे की स्थिति में भी कम नुकसान हुआ। अतिरिक्त वर्षा का पानी नाली की सहायता से खेत से बाहर निकल गया जिससे फसल खराब होने की संभावना काफी कम हो गई।

श्री जसमाल के खेतों में विगत वर्ष की तुलना में लगभग 12-15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ज्यादा उत्पादन हुआ। प्रति क्विंटल 1800 रुपये की दर से फसल बेचने पर उन्हें 15 से 20 हजार रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है।

इसी तरह विकासखण्ड राजगढ़ के ग्राम भाटपुरा के श्री शंकर सिंह ने अपनी 2 हेक्टेयर कृषि भूमि पर पानी की समस्या हल कर ली है। उन्होंने लाइनिंग फार्म पोंड बनवाया, जिससे खेतों की सिंचाई के लिए आसानी से पानी सुलभ हुआ। पैदावार में बढ़ोत्तरी होने से अब वे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं।

विकासखण्ड राजगढ़ के ही कृषक श्री मांगीलाल की ग्राम बेडाकापुरा के पास 0.450 हेक्टेयर भूमि पर सोयाबीन की खेती के लिए कृषि विभाग द्वारा सोयाबीन के नि:शुल्क उन्नत बीज और मार्गदर्शन दिया गया। नतीजे में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उन्होंने 6 से 8 क्विंटल का अधिक उत्पादन लिया। मांगीलाल को प्रति क्विंटल साढ़े 3 हजार के मान से 17 से 23 हजार रुपये तक की अधिक आमदनी हुई है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

अपने आप में सम्पूर्ण और मानवीय भावनाओं से भरपूर हों प्रदेश के शहर ....

प्रदेशवासियों की जिंदगी बदलना हमारा मकसद और लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आईए हम सब मिलकर कार्य करें। सरकार के साथ समाज की शक्ति मिले और हम साथ मिलकर शहरों को बदल दें, यही हमारा संकल्प है। हमारे शहर रोजगार युक्त, विकसित, स्वच्छ शहर बनें। ऐसे शहर बनाने के लिए हम मिलकर कदम बढ़ाएँ।

मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के हितग्राहियों के गृह प्रवेश, भूमि-पूजन एवं किश्त वितरण के लिए कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केंद्र, भोपाल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या-पूजन और दीप जला कर किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वर्चुअली 50 हजार आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया, साथ ही 1155 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 30 हजार नवीन आवासों का भूमि-पूजन तथा 26 हजार 500 हितग्राहियों के खातों में 250 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से अंतरित किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद किया तथा नगर निगम भोपाल के 5 हितग्राहियों को आवास आवंटन आदेश तथा आवास आधिपत्य-पत्र प्रदान किये।

कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने वर्चुअली सहभागिता की। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरपाल सिंह डंग, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया, सांसद श्री वी.डी. शर्मा, विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, श्रीमती कृष्णा गौर, पूर्व महापौर श्री आलोक शर्मा, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री मनीष सिंह, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज श्रीवास्तव उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न भागों में सम्पन्न गृह प्रवेश की झलकियों पर केन्द्रित लघु फिल्म "साकार हो रहा अब सपना- सबका हो रहा घर अपना" का प्रदर्शन भी किया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन गरीब भाई-बहनों का मकान बनने का सपना आज साकार हो रहा है, उनके लिए यह दिन अद्भुत है। हर व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि उसका अपना मकान हो। आज 1 लाख 6 हजार से अधिक भाई-बहनों का यह सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, सम्पन्न, शक्तिशाली और आत्म-निर्भर भारत के निर्माण के लिए संकल्पित हैं। इस क्रम में राज्य सरकार भी आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए कार्यरत है। इसके लिए शहरों को आत्म-निर्भर बनाना आवश्यक है। शहर विकास का इंजन होते हैं, यह कई लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन आसान कैसे बनाया जाए, यह बिंदु हमारी सोच के केंद्र में सदैव प्रमुखता से रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शहरों के विकास के लिए कई मंत्र दिए हैं। पहला मंत्र - हर नगर, राज्य के विकास का चेहरा बने। दूसरा मंत्र - शहरों में जीवन जीना सभी के लिए आसान हो। तीसरा मंत्र - हर नगरवासी को बेहतर से बेहतर जीवन की गुणवत्ता मिले। चौथा मंत्र - शहरों के आकार भले ही बढ़ जाएँ, लेकिन असमानताएँ कम होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी का पाँचवां मंत्र - शहर ऐसा हो कि यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आत्म-सम्मान के साथ जीवन-यापन का अवसर उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री के इन मंत्रों पर राज्य सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान, पढ़ाई-दवाई और रोजगार प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्राण-प्रण से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर गरीब को जीने का अधिकार है। धरती के सभी संसाधन सभी लोगों के लिए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवासहीन परिवारों को पट्टे देने का कार्य आरंभ किया गया। राशन वितरण की भी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 4 करोड़ 80 लाख लोगों को नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में भी राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में अब तक 8 लाख 68 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 4 लाख 72 हजार हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों के लिए तीन प्रकार के विकल्प हैं - प्रथम विकल्प में हितग्राही आधारित स्वयं निर्माण घटक में हितग्राही के द्वारा आवास का निर्माण स्वयं किया जाता है। दूसरा विकल्प पीएचए घटक है जिसमें नगरीय निकायों द्वारा आवासों का निर्माण कर हितग्राहियों को आवास आवंटित किए जाते हैं। तीसरा विकल्प ऋण आधारित सबसिडी का है। राज्य सरकार का यह संकल्प है कि प्रदेश में प्रत्येक गरीब को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में शहरी हो या ग्रामीण, रहने के लिए जमीन का टुकड़ा हर व्यक्ति को चाहिए। जिनके पास जमीन का टुकड़ा नहीं है उन्हें मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना में पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाने का अभियान राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। रसोई गैस का सिलेंडर,पीने का पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएँ हर घर को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज के कार्यक्रम में जिन्हें आवास मिला है उन्हें बधाई दी और कहा कि जिन्हें अब तक आवास नहीं मिला उन्हें भी आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की अवैध कालोनियों को वैध कालोनी में परिवर्तित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नगरीय निकाय की प्रतिनिधियों से स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए सजग और सतर्क रहकर कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। शासकीय अधिकारियों के साथ स्वच्छता अभियान में जनता के जुड़ने से ही परिणाम आते हैं। अत: समाज के हर वर्ग को स्वच्छता अभियान से जुड़कर अपने नगरीय निकाय को स्वच्छता में सर्वोच्च लाने का प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी धर्मगुरुओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, रहवासी संघों, स्वंयसेवियों, सफाई कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे अपने शहर को कम से कम थ्री स्टार रेटिंग में लाने का प्रयास अवश्य करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक गाँव और शहर की अपनी संस्कृति, संस्कार और मूल्य होते हैं। अत: सभी 407 नगरीय निकाय साल भर में किसी एक दिन अपने नगर का जन्म दिवस अथवा गौरव दिवस अवश्य मनाएँ। भोपाल का जन्म-दिवस विलीनीकरण दिवस 1 जून को तथा इंदौर का जन्म दिवस माँ अहिल्या के जन्म दिवस पर मनाया जाएगा। जन्म दिवस अथवा गौरव दिवस पर अपने गाँव और शहर के सभी लोगों को आमंत्रित करें और अपने क्षेत्र के विकास की योजनाएँ बनाएँ। साथ ही अन्य कई प्रकार की गतिविधियाँ संचालित की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अपने शहरों को आगे बढ़ाने के लिए जज्बा और जुनून आवश्यक है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में भोपाल के श्री लखन सिंह राजपूत, श्री मुकेश चौहान, श्रीमती राजकुमारी शाक्य को आवास आवंटन प्रमाण-पत्र तथा श्री रणवीर अहिरवार और श्री बाबूलाल गौर को आवास आवंटन प्रमाण-पत्र तथा गृह प्रवेश के प्रतीक स्वरूप घर की चाबी भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने धार जिले की बदनावर नगर परिषद की श्रीमती तीजा बाई, रतलाम जिले की जावरा नगर परिषद की श्रीमती फरजाना, अनूपपुर की जेतहरि नगर परिषद के श्री दोलू कोल और भिण्ड के महगाँव की श्रीमती गंगाबाई से वर्चुअली संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हितग्राहियों से प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं के मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन की भी जानकारी प्राप्त की।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के हर गरीब के अपने घर के सपने को साकार कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकाल कर समृद्धशाली राज्यों में स्थान दिलाया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रदेश में क्रियान्वित नगरीय विकास के कार्यक्रमों में तीन बार सहभागिता की है। यह प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। प्रदेश के शहरों को मुख्यमंत्री श्री चौहान की संकल्पना के अनुरूप स्वच्छ, सुन्दर और विकसित बनाने के लिए विभाग कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

खजुराहो सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के गरीबों के जीवन बदलने के अभियान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को क्रियान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में संचालित योजनाओं का बेहतर प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कोरोना संकट में भी प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में छह माह से कम अवधि में मकान बनकर तैयार हुए हैं। यह उपलब्धि सरकार की गति और संकल्प को दर्शाती है। नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया ने आभार माना।

मानव संसाधन हेतु आउट सोर्स कर्मचारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न

भोपाल। म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें म.प्र. द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी संघ को मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके तहत राज्य समन्वयक/ समन्वयक/डाटा एन्ट्री आपरेटर / लिपिक/तकनीकी सहायक/ भृत्य/वाहन चालक एवं सुरक्षा गार्ड को कार्य दायित्व पर आधारभूत प्रशिक्षण संघ के श्री संजय सिंह, ओ.एस.डी, श्री ए.के. जोशी, भू.पू.प्राचार्य, श्री जी.पी. मांझी, प्राचार्य, श्री सुरेशचन्द्र वर्मा सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रमाण पत्र वितरण संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन के द्वारा किया गया

तीन दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण का समापन

सीहोर। दिनांक 12.02.2022 को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ मर्यादित नई दिल्ली एवं जिला सहकारी संघ मर्यादित सीहोर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित तीन दिवसीय सहकारी नेतृत्व विकास कार्यक्रम के समापन दिवस पर डॉ. प्रज्ञा नेमा प्रभारी सिविल सर्जन पशु चिकित्सालय सीहोर द्वारा पशुओं को होने वाली बिमारियों खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, पेट में होने वाले कीड़ों से बचाव एवं उसके उपचार के बारे मे बताया तथा प्रति वर्ष पशुओं में लगने वाले विभिन्न बिमारियों के टीके लगाने पर जोर दिया, जिससे पशुओं में होने बिमारियों से बचाया जा सके एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन पर प्रकाश डाला। कृपाल सिंह दुगारिया जिला नोडल अधिकारी भोपाल दुग्ध सहकारी संघ मर्यादित भोपाल द्वारा दुधारू पशुओं के शासन द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में समझाया तथा उसके सही उपयोग के लिए समझाया। श्री के. एल. राठौर पूर्व प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर द्वारा सहकारी संस्थाओं में की जाने वाली बैठकों के नियम एवं पारित प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री निरन्जन कुमार कसारा पूर्व प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर द्वारा नेतृत्व विकास के विभिन्न चरण के बारे में बताया। श्री एस. के. सक्सेना प्रशासक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता विभाग सीहोर द्वारा सहकारी संस्थाओं में संचालक मण्डल के दायित्व को बताया। तेजसिंह ठाकुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सहकारी सिद्धांत एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए आभार प्रकट किया। इस अवसर पर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था निपानियाकलॉ, करंजखेड़ा, मुहाली, सेमरादांगी, लालाखेड़ी, चितावलिया लाखा के संचालक मण्डल के सदस्य उपस्थित हुए। तीन दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त किया।

गबन, धोखाधड़ी एवं अंकेक्षण तथा विभागीय कार्य निष्पादन पर वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं सहकारी निरीक्षकों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन

भोपाल। सहकारी संस्थाओं में गबन, धोखाधड़ी एवं अंकेक्षण तथा विभागीय कार्य निष्पादन विषय पर दिनांक 21.02.2022 से 23.02.2022 तक कुल 18 प्रतिभागियों ने भारतीय दण्ड संहिता के तहत गबन, धोखाधड़ी, अमानत में खयानत की व्याख्या एवं प्रावधान विषय पर श्री डी. के. सक्सेना, आर्थिक अपराध शाखा/ अधिवक्ता, वर्तमान में प्रदेश में प्राप्त महत्वपूर्ण गबन अपराधियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं अपराध पूर्व रोकथाम, विषय पर श्री अविनाश सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, भारतीय दण्ड संहिता के तहत पुलिस में एफ.आई. आर. दर्ज कराने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं दस्तावेज व गबन, धोखाधडी, अमानत में खयानत आदि प्रकरणों का न्यायालयीन निर्णय हेतु प्रमुख तथ्य समस्या एवं समाधान विषय पर पर श्री के के सक्सेना, से.नि. डिप्टी डायरेक्टर, प्रोसिक्यूशन , संस्थाओं के वित्तीय पत्रकों का परीक्षण, तकनीकी पैरामीटर के आधार पर– सी.आर., ए.आर., एन.पी.ए. एवं अन्य पैरामीटर पर कर प्रतिवेदन दर्ज करना विषय पर श्री पी.के.एस. परिहार, वरिष्ठ प्रबंधक अपेक्स बैंक, संस्थाओं के अंकेक्षण में सी.बी.एस. एवं डी.एम.आर. एकाउंट का परीक्षण करना एवं वित्तीय अनियमित्ताओं की जानकारी प्राप्त करना विषय पर श्री आर.के. गंगेले, ओ.एस.डी., अपेक्स बैंक, संस्थाओं के वित्तीय पत्रकों के परीक्षण–निरीक्षण एवं टैक्स लायबलिटी (जी.एस.टी., आयकर आदि) का परीक्षण एवं अंकेक्षण टीप में शामिल किया जाना विषय पर अंशुल अग्रवाल, चार्टड एकाउंटेंट, सहकारी संस्था को हुई हानि की पूर्ति हेतु की जाने वाली विधिक कार्यवाही एवं पृथक वैधानिक प्रतिवेदन की जानकारी व कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यनिष्पादन, कर्तव्य, उत्तरदायित्व व द्वारा प्रशासक निर्वाचन अधिकारी, परिसमापन, अंकेक्षण श्री श्रीकुमार जोशी, सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त सहकारिता, सहकारी संस्थाओं में गबन एवं धोखाधडी के मुख्य प्रकार एवं उनके तथ्यों का प्रकटीकरण पर श्री प्रदीप नीखरा सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त सहकारिता, वर्तमान में संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु जारी अद्यतन परिपत्र एवं उनका पालन कर वित्तीय अनियमितताओं पर रोकथाम विषय पर श्री संजीव गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, वर्क लाईफ बैलेंस, व्यक्तित्व विकास, संवैगात्मक बुद्धि, समय एवं तनाव प्रबंधन विषय पर श्री राजेन्द्र सक्सेना, कारपोरेट मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के समापन अवसर पर श्री गणेश प्रसाद मांझी, प्राचार्य ,श्री संतोष येड़े, राज्य समन्वयक, कार्यक्रम का संचालन श्रीमती रेखा पिप्पल के द्वारा किया गया। श्री विनोद कुशवाहा, श्री लोकेश श्रीवास्तव, श्री विक्रम मुजुमदार, श्री प्रवीण कुशवाह, श्री धनराज सैंदाणे, श्री ज्ञानू सिंह एवं समस्त स्टाफ का विशेष सहयोग रहा।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।